भारत सरकार

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2814

17.12.2025 को उत्तर देने के लिए

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

2814. श्री तमिलसेल्वन थंगाः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) संकलन ढांचे में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से निःशुल्क वितरित की जाने वाली वस्तुओं के संबंध में एक संवाद पत्र जारी किया है और विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, सरकारी निकायों, राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थानों और अन्य हितधारकों से विचार आमंत्रित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) आज की तिथि के अनुसार विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, सरकारी निकायों, राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थानों और अन्य हितधारकों से प्राप्त प्रतिक्रिया/विचारों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार वर्तमान में सीपीआई में संशोधन कर रही है और उसने सीपीआई आधार वर्ष को वर्ष 2012 से 2024 तक संशोधित करने की प्रक्रिया भी आरंभ कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सीपीआई को संशोधित करने की संभावित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह)

(क) और (ख): उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) संकलन में नि:शुल्क पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) वस्तुओं के विषय में एक चर्चा पत्र दिनांक 4 अक्टूबर, 2025 को विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और उपयोगकर्ताओं से टिप्पणियाँ और प्रतिक्रियाएँ प्राप्त करने के लिए प्रकाशित किया गया था। ये टिप्पणियाँ सुदृढ़ कार्यप्रणालियों, प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों, मौद्रिक नीति संबंधी आशयों और प्रस्ताव के आर्थिक तर्कों पर हैं।

(ग) और (घ): इस मंत्रालय ने बाजारों और वस्तुओं के संदर्भ में सीपीआई का कवरेज बढ़ाने, कार्यप्रणाली में सुधार करने, उद्देश्य के अनुसार व्यक्तिगत उपभोग वर्गीकरण 2018 (सीओआईसीओपी) को अपनाने और सीपीआई में प्रशासनिक तथा ऑनलाइन डेटा के समावेशन के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के मौजूदा आधार वर्ष 2012 को नए आधार वर्ष 2024=100 में बदलने हेतु आधार संशोधन किया है। नई सीपीआई श्रृंखला का पहला प्रकाशन, 2024=100 आधार के साथ, दिनांक 12 फरवरी, 2026 को किया जाएगा।

****